भारत सरकार
नागर विमानन मंत्रालय
लोक सभा
लिखित प्रश्न संख्या : 1984
गुरुवार, 30 जुलाई, 2026/8 श्रावण, 1948 (शक) को दिया जाने वाला उत्तर

तमिलनाडु में विमानपतनों का विस्तार

1984. डॉ. कलानिधि वीरास्वामीः

क्या **नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) वर्तमान में चेन्नई सहित तमिलनाडु में कार्यान्वित किए जा रहे विमानपतनों के विस्तार एवं आधुनिकीकरण परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) प्रत्येक परियोजना की वर्तमान स्थिति, उसकी अनुमानित लागत, स्वीकृत निधि, जारी की गई निधि, किए गए व्यय तथा उसके पूर्ण होने की निर्धारित तिथि क्या है;

(ग) क्या तमिलनाडु में किसी विमानपतन विस्तार परियोजना में विलंब अथवा लागत वृद्धि की स्थिति बनी है, यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) इन विस्तार परियोजनाओं के पूर्ण होने के उपरांत यात्री वहन क्षमता में अनुमानित वृद्धि कितनी होगी तथा तमिलनाडु से घरेलू एवं अंतरराष्ट्रीय हवाई संपर्क में सुधार के लिए क्या उपाय प्रस्तावित किए गए हैं; और

(ङ) तमिलनाडु में हवाई अड्डा अवसंरचना परियोजनाओं को समय से पूरा करने तथा बेहतर यात्री और कार्गो सुविधाएं एवं रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर
नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुरलीधर मोहोल)

(क) से (घ) मौजूदा हवाईअड्डों का उन्नयन/आधुनिकीकरण एक सतत प्रक्रिया है और इस कार्य को भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) और अन्य हवाईअड्डा प्रचालकों द्वारा यात्री मांग, प्रचालन संबंधी अपेक्षाओं और एयरलाइन की मांग के आधार पर किया जाता है।

तमिलनाडु में हवाईअड्डों पर प्रमुख विस्तार और विकास कार्यों में शामिल हैं:

चेन्नई हवाईअड्डा: यात्री प्रबंधन क्षमता को 30 मिलियन यात्री प्रति वर्ष (एमपीपीए) से बढ़ाकर 35 एमपीपीए करने के लिए 2,467 करोड़ रुपये की लागत से चरण-2 का आधुनिकीकरण। जून, 2026 तक लगभग 1,762.08 करोड़ रुपये व्यय किए गए हैं। तूफानी जल निकासी सुधार (209.01 करोड़ रुपये), टर्मिनल 1 का नवीनीकरण (81.8 करोड़ रुपये) और एयरसाइड अवसंरचना का विकास (480.06 करोड़ रुपये) जैसे अतिरिक्त कार्य किए गए हैं।

तिरुचिरापल्ली हवाईअड्डा: लगभग 80.17 करोड़ रुपये की लागत के नए एटीसी टॉवर-सह-तकनीकी ब्लॉक कार्य, जिसमें जून 2026 तक लगभग 39.06 करोड़ रुपये का व्यय हुआ है;

कोयंबटूर हवाईअड्डा: नव अधिग्रहित भूमि पर चारदीवारी का निर्माण और मौजूदा टर्मिनल भवन में परिवर्धन और परिवर्तन का कार्य क्रमशः 51.31 करोड़ रुपये और 13.71 करोड़ रुपये की लागत से आरंभ हो गया है।

हवाईअड्डा विस्तार परियोजनाओं को कभी-कभी भूमि अधिग्रहण चुनौतियों, लंबित सांविधिक और पर्यावरणीय मंजूरियां, विकासकर्ताओं द्वारा वित्तीय समापन, और प्रतिकूल मौसम, जलभराव, आदि सहित अप्रत्याशित साइट-विशिष्ट मुद्दों के कारण देरी का सामना करना पड़ता है।

मार्च 1994 में घरेलू विमानन क्षेत्र को नियंत्रणमुक्त किए जाने के बाद से, एयरलाइनें परिचालन और वाणिज्यिक व्यवहार्यता के आधार पर अपने विमानों की तैनाती और मार्ग नेटवर्क का निर्धारण करती हैं। तदनुसार, हवाई सेवाओं की शुरुआत करना एयरलाइनों के विवेक पर निर्भर करता है। अंतरराष्ट्रीय हवाई सेवाएं भारत और संबंधित देशों के बीच द्विपक्षीय हवाई सेवा समझौतों (एएसए), वाणिज्यिक व्यवहार्यता, यात्री मांग, स्लॉट उपलब्धता, परिचालन व्यवहार्यता और अन्य संबंधित कारकों द्वारा शासित होती हैं।

(ङ) : अवसंरचना परियोजनाओं में हुए विलंब का समाधान करने के लिए, नागर विमानन मंत्रालय और भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) परियोजना प्रभारियों और निष्पादन एजेंसियों के समन्वय में परियोजना की नियमित समीक्षा करते हैं।

******